इंपैक्ट प्लेयर नियम पर अधिकांश आईपीएल कप्तानों ने अपनी आपत्ति जताई

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

आईपीएल के अधिकांश कप्तानों ने बुधवार को इंपैक्ट प्लेयर नियम पर अपनी आपत्ति जताई, जिसने 2023 में लागू होने के बाद से ही अलग-अलग राय पैदा की है। 2024 में बीसीसीआई ने इस नियम को आईपीएल में कम से कम 2027 तक बढ़ा दिया था।

इसके बावजूद यह रणनीतिक नियम प्रशंसकों और खिलाड़ियों के बीच लगातार बहस का विषय बना हुआ है। मुंबई में हुई आईपीएल कप्तानों की बैठक में सभी 10 फ्रेंचाइजियों के कप्तानों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। एक आईपीएल सूत्र ने कहा कि अधिकांश कप्तानों ने इंपैक्टर प्लेयर नियम पर अपने सुझाव दिए और आपत्तियां जताईं। हालांकि, बीसीसीआई इसे 2027 तक बढ़ा चुका है। उन्हें बताया गया कि इस नियम की समीक्षा 2027 संस्करण के बाद ही की जा सकती है, उससे पहले नहीं।

इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने रोहित शर्मा की तरह इस नियम की आलोचना की थी। अक्षर ने कहा कि मुझे यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऑलराउंडर हूं। पहले हम इस भूमिका के लिए ऑलराउंडर चुनते थे। अब टीम मैनेजमेंट किसी खास बल्लेबाज या गेंदबाज को चुन लेता है और कहता है कि हमें ऑलराउंडर की जरूरत ही क्या है।

2024 में रोहित शर्मा ने भी कहा था कि वह इंपैक्ट प्लेयर अवधारणा के पक्ष में नहीं हैं, इससे भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडरों के विकास पर असर पड़ता है। अगले सीजन में हार्दिक पांड्या ने कहा था कि अब टीम में ऑलराउंडर चुनना मुश्किल हो गया है, जब तक वह बल्ले और गेंद दोनों से बराबर अच्छा प्रदर्शन न करे।

पहली पारी के 10 ओवर बाद गेंद बदलने की मांग

पिछले सीजन बीसीसीआई ने ओस के प्रभाव को कम करने के लिए दूसरी पारी के 10 ओवर बाद एक बार गेंद बदलने की अनुमति दी थी। बुधवार को एक कप्तान ने प्रस्ताव रखा कि पहली पारी के 10 ओवर बाद भी गेंद बदलने की अनुमति दी जाए। सूत्र ने कहा कि पहली पारी के 10 ओवर बाद गेंद बदलने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला। आमतौर पर दूसरी पारी में ज्यादा ओस होती है। इसलिए मौजूदा नियम ही जारी रहेगा।

आईपीएल ने पूरे लीग चरण का शेड्यूल किया जारी

नई दिल्ली, आरएनएन। आईपीएल 2026 का लीग चरण 24 मई तक चलेगा। बीसीसीआई ने शुरुआती शेड्यूल के बाद गुरुवार को लगभग पूरे लीग कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, हालांकि प्लेऑफ के वेन्यू पर अभी सस्पेंस बरकरार है।

टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को होगी, जब डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइज़र्स हैदराबाद से होगा। 11 अप्रैल तक के शुरुआती दौर के लिए 20 मैच पहले ही तय थे। नए शेड्यूल के अनुसार, 13 अप्रैल से 24 मई के बीच देश के 12 मैदानों पर कुल 50 मैच खेले जाएंगे।

इसमें रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम भी शामिल है, जिसे आरसीबी ने अपना दूसरा होम ग्राउंड चुना है। आरसीबी यहां 10 मई को मुंबई इंडियंस और 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेंगे। इस बार धर्मशाला भी आईपीएल कैलेंडर में वापसी कर रही है। पिछले साल भारत-पाक सीमा तनाव के कारण दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच रद्द किया गया था।

इस साल 11 मई को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान उसी पुरानी भिड़ंत (दिल्ली वर्सेस पंजाब) के साथ वापसी करेगा। पुराने शेड्यूल में केवल तीन डबल-हेडर थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर आठ कर दी गई है।

एसोचैम का अनुमान, आंतरिक मांग से देश की वृद्धि दर को मिलेगी मजबूती

वैश्विक संकट के बावजूद भी भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में ऊंची बनी रहेगी

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

भारत के प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक संकटों के चलते आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यवधान से वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मंद हो सकती है पर भारत आंतरिक उपभोग और निवेश मांग की बदौलत अगले वित्त वर्ष 2026-27 सात प्रतिशत से ऊपर की तेज गति से वृद्धि की राह पर बना रहेगा।

एसोचैम का मानना है कि 2026 में वैश्विक वृद्धि दर नरम पड़ कर 3 प्रतिशत से नीचे रह सकती है। संगठन ने आगाह किया है कि चूँकि रुपये के मूल्य में काफ़ी गिरावट आई है, इसलिए घरेलू बाजार में एलपीजी सिलेंडरों जैसे कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसका असर आने वाले समय में महँगाई के रुझानों पर देखने को मिलेगा। उद्योग मंडल ने गुरूवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पश्चिम एशिया युद्ध के असर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम असरदार और सही समय पर हैं। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में 7.6 प्रतिशतकी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

मिंडा ने कहा कि पिछले कई सालों से सुधारों के ज़रिए सरकार का मज़बूत समर्थन बिज़नेस के भरोसे को बढ़ाता है। घरेलू खपत का रुझान कई सालों के सबसे ऊँचे स्तर पर है, जिसे कर व्यवस्था में सुधार और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) में किए गए साहसी सुधारों से समर्थन मिला है, और निवेश भी उसी रफ़्तार से बढ़ रहा है। श्री मिंडा ने कहा, 'आगे उम्मीद है कि भारत की वृद्धि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में सात प्रतिशत से ऊपर बना रहेगा, जबकि ग्लोबल ग्रोथ के तीन प्रतिशत से नीचे गिरने का डर है।'

एसोचैम का कहना है कि 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग 7.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है, और आने वाले वित्त वर्ष, 2026-27 में 7 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि की उम्मीद है भू-राजनीतिक और अमेरिका में ऊंचे शुल्क से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, भारत की वृद्धि दर पिछले तीन सालों में सात प्रतिशत से ज़्यादा की रही है। फरवरी 2026 के महीने में भारत का विनिर्माण क्षेत्र संबंधी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) 56.9 और सेवा क्षेत्र पीएमआई 58.1 पर रहा जो दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका , चीन और जर्मनी) में सबसे ज़्यादा रहे।

निर्यात में अप्रैल से फरवरी 2025-26 के दौरान लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह बढ़कर 791 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रत्न और आभूषण, तथा कृषि उत्पादों से एक्सपोर्ट को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। भारत के पास विकसित, उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपने व्यापार को विविध बनाने के कई अवसर मौजूद हैं।

एसोचैम ने कहा है कि भारत के रत्न और आभूषण क्षेत्र ने पश्चिम एशिया को लगभग 8.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिसमें दुबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। लॉजिस्टिक्स में आने वाली बाधाओं के कारण शिपमेंट में देरी हो सकती है, जिससे व्यापारियों और निर्माताओं की लागत बढ़ सकती है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों का भारत के फार्मा निर्यात में लगभग 5.6 प्रतिशत हिस्सा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गहरा असर

पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। ऊर्जा आपूर्ति -ृंखलाओं में आने वाली बड़ी रुकावटों के कारण विश्व के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 3 प्रतिशत से भी नीचे गिर सकती है। पश्चिम एशिया तेल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरकों और एल्युमीनियम का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों का असर ऊर्जा, ऑटोमोटिव, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, तथा कृषि और खाद्य आपूर्ति -ृंखलाओं पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसका वैश्विक जीडीपी में लगभग 11 प्रतिशत योगदान है, और इसका असर वैश्विक विकास पर भी पड़ेगा। अनुमान है कि कुल मिलाकर, अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की वृद्धि दर नौ प्रतिशत रही

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

देश का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र वार्षिक आधार पर लगभग नौ प्रतिशत की दर से मजबूत वृद्धि दर्ज हासिल कर रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की राशि 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार यह वृद्धि बढ़ती जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण तक बेहतर पहुंच और चिकित्सा खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

पॉलिसीधारकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावों के प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की है। आईआरडीएआई

द्वारा कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन एक घंटे के भीतर और अंतिम स्वीकृति - तीन घंटे के भीतर किए जाने के निर्देश हैं। इन समय-सीमाओं का उद्देश्य देरी को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को समय पर चिकित्सा देखभाल मिल सके ।

आईआरडीएआई के 2024 के नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बीमा उत्पादों का मूल्य निर्धारण सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों के आधार पर उचित रूप से किया जाए और वे व्यवहार्य और मूल्य-संचालित बने रहें, साथ ही नियुक्त बीमांकिक द्वारा डेटा और ग्राहक प्रतिक्रिया का उपयोग करके आवधिक समीक्षा की जाए।

जियो फाइनेंशियल एलियांज की साझा रीइंश्योरेंस कंपनी शुरू

मुंबई, आरएनएन। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड और एलियांज़ ग्रुप के संयुक्त उद्यम एलियांज़ जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड ने भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) से गत 12 मार्च को अंतिम नियामकीय मंजूरी मिली थी।

मुंबई स्थित यह संयुक्त उद्यम जियो फाइनेंशियल की स्थानीय पहुंच और डिजिटल नेटवर्क को एलियांज़ की वैश्विक अंडरराइटिंग विशेषज्ञता के साथ जोड़कर बीमा कंपनियों को जोखिम प्रबंधन क्षमता उपलब्ध कराएगा। जियो फाइनेंशियल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेश सेठिया ने कहा कि यह एलियांज़ के साथ व्यापक बीमा साझेदारी की दिशा में पहला कदम है।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

मौजूदा OHE में OHE संशोधन और अन्य संबंधित TRD कार्य

निविदा सूचना सं. इएल-टीआरडी-टेंडर-25-26-35 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या और कार्य का नाम: इएल-टीआरडी-टेंडर-25-26-35** विश्वमित्री स्टेशन पर मौजूदा ओएचई में ओएचई में संशोधन एवं अन्य संबंधित टीआरडी कार्य प्लेटफार्म के विस्तार और स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित करने, रानोली-बाजवा के अंतिम छोरों को जोड़ना और वडोदरा स्टेशन पर वडोदरा, अहमदाबाद एवं गोधरा के लिए दोनों को प्रेषण के लिए स्टार्टर सिग्नल के संबंध में ओएचई में संशोधन कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत (रू):** ₹ 6,96,01,383.14/- **बोली प्रतिभूति (रु):** ₹ 4,98,000/- **निविदा की राशि एवं कार्य समापन की अवधि:** कार्य समापन की अबाधि 18 माह **निविदा की समय सारणी:** निविदा बंद होने का दिनांक एवं समय 20/04/2026, 15-00 बजे **वेबसाइट विवरण और सूचना का लोकेशन जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा कार्यालय का पता विवरण जानकारी के लिये:** वेबसाइट **विवरण www.ireps.gov.in** मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वड़ोदरा - 390004 **BRC 405**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

इंडसइंड बैंक ने पेश किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम

मुंबई, आरएनएन। इंडसइंड बैंक ने गुरुवार को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पेश की, जिसके तहत ग्राहक पुनर्निवेश तक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को जमा रख सकते हैं और इस दौरान आयकर कानून के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

बैंक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह योजना पूंजीगत लाभ को पुनर्निवेश तक सुरक्षित और नियमों के अनुरूप रखने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे ग्राहक निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर सोच-समझकर उस पूंजी को दोबारा निवेश करने के बारे में निर्णय ले सकेंगे। यह योजना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से अनुमति मिलने के बाद पेश की गयी है। बोर्ड ने इंडसइंड बैंक को पूंजीगत लाभ योजना, 1988 के अंतर्गत जमा स्वीकार करने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत, बैंक पात्र पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त अप्रयुक्त राशि को जमा के रूप में स्वीकार करेगा।

, जिसमें आवासीय संपत्तियां, फ्लैट, फार्महाउस, कृषि भूमि, शहरी भूमि और विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की भूमि शामिल हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत इंडसइंड बैंक दो प्रकार के खाते प्रदान करता है - बचत खाता और सावधि जमा खाता। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार, खाते का चयन कर सकते हैं। यह योजना अधिकृत गैर-ग्रामीण

म्यूचुअल फंड्स हाउसेज रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड्स ग्राहकों को पेश करते रहेंगे

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

सेबी ने शर्तों के साथ दी इजाजत

नई दिल्ली, आरएनएन। म्यूचुअल फंड्स हाउसेज रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड्स ऑफर करते रहेंगे। सेबी ने 20 मार्च को इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन, सेबी ने लाइफ साइकिल फंड्स के मामले में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले 26 फरवरी को इश्यू सर्कुलर के जरिए रेगुलेटर ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद कुछ चिंता जताई गई थी। सेबी ने अब स्पष्ट किया है कि अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी चिल्ड्रेंस फंड जारी रखने का फैसला लेती है तो वह 20 साल की अवधि वाला लाइफ साइकिल फंड लॉन्च नहीं कर सकेगी। इसी तरह अगर कोई एएमसी रिटायरमेंट फंड को जारी रखना चाहती है तो वह 30 साल की अवधि वाला लाइफ साइकिल फंड लॉन्च नहीं कर सकेगी। अगर कोई एएमसी रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड दोनों जारी रखना चाहती है तो वह 20 साल और 30 साल वाले लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है कि वह सिर्फ 5, 10,15 और 25 साल वाले लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर सकेगी।कोई एएमसी अगर रिटायरमेंट और चिल्ड्रेंस फंड जारी नहीं रखना चाहती है तो वह सभी छह तरह के लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर सकेगी। ऐसे मामलों में रिटायरमेंट और चिल्ड्रेंस फंड में नए सब्सक्रिप्शन पर रोक रहेगी ।

सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होने पर इंडस्ट्री ने जताई थी चिंता

जानकारों के मुताबिक एंफी रिटायरमेंट और चिल्ड्रेंस फंड बंद करने के रेगुलेटर के फैसले के बारे में सेबी को एक रिप्रजेंटेशन देगा। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय कहा था कि वह इंडस्ट्री की चिंता पर विचार कर रहे हैं। एंफी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना संख्या: झाँसी-इन्जी0-ई-2026-61 **दिनांक:** 25.03.2026

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झाँसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिगं) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।

कार्य का नाम : झाँसी डिवीज़नः- कंस्ट्रक्शन ऑफ़ आरपीएफ बैरक फॉर 20 बेडेड कैपेसिटी कैपेसिटी अलोंग विथ मेस, टॉयलेट, बाथरूम ईटीसी फॉर आरपीएफ/आरपीएसएफ स्टाफ एट बाँदा।

अनुमानित लागत (रू): ₹ 19916162.45 | **अमानत राशि (रू):** ₹ 398300.00

निविदा बन्द होने की तिथि: 20.04.2026 at 15:00 hrs.

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि: 12 माह

● निविदा **दिनांक 20.04.2026** को **15.00 बजे** तक आन लाईन जमा कर सकेगें।
● पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के बेवसाईट www.ireps.gov.in पर देखें। **670/26 (A)**

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

मांग पहली तिमाही में हुआ 15 प्रतिशत का इजाफा

ऑफिस मार्केट की मांग में मजबूत बढ़ोतरी

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के शीर्ष सात शहरों में ऑफिस मार्केट ने वर्ष 2026 की शुरुआत मजबूत रफ्तार के साथ की है। पहली तिमाही में 183 लाख वर्ग फुट की लीजिंग दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ती मांग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विस्तार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद इस गति को बनाए रखा है।

बेंगलूरु और हैदराबाद ने मिलकर कुल तिमाही लीजिंग का लगभग आधा हिस्सा यानी 87 लाख वर्ग फुट योगदान दिया। वहीं मुंबई, पुणे, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई जैसे शहरों में ग्रेड-ए स्पेस की मांग मजबूत रही, जहां प्रत्येक शहर में 20 से 30 लाख वर्ग फुट के बीच लीजिंग हुई। खास बात यह

रही कि हैदराबाद और पुणे में ऑफिस स्पेस की मांग सालाना आधार पर दोगुने से अधिक बढ़ी।

जानकारों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शीर्ष सात बाजारों में 183 लाख वर्ग फुट ग्रेड-ए स्पेस की लीजिंग भारत के ऑफिस बाजार की मजबूती को दर्शाती है। मांग में जीसीसीएस का योगदान आधा रहा। भले ही वैश्विक चुनौतियां प्रोजेक्ट पूर्णता की समय-सीमा को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन मांग का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। दीर्घकालिक जीसीसी विस्तार, विविध ऑक्युपायर बेस, फ्लेक्स स्पेस की बढ़ती पेशकश और उच्च गुणवत्ता वाले एसेट्स की बढ़ती पसंद के कारण भारतीय ऑफिस बाजार एशिया-प्रशांत यानी एपीएसी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल रहेगा।

टेक्नोलॉजी कंपनियों की 36 प्रतिशत हिस्सेदारी

2026 की पहली तिमाही में पारंपरिक ऑफिस स्पेस में 144 लाख वर्ग फुट की लीजिंग हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी और बीएफएसआई सेक्टर ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन दोनों सेक्टरों ने मिलकर 95 लाख वर्ग फुट यानी कुल पारंपरिक मांग का लगभग दो-तिहाई हिस्सा लिया। बीएफएसआई की मांग में बेंगलूरु और मुंबई अग्रणी रहे, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियों की मांग का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बेंगलूरु और हैदराबाद से आया। फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटरों की लीजिंग में भी 77 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज हुई और यह करीब 40 लाख वर्ग फुट रही। दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद ने मिलकर फ्लेक्स स्पेस लीजिंग का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लिया।

सरसों में सुधार से बाकी तेल तिलहन के दाम में मजबूती

नई दिल्ली, आरएनएन। किसानों की ओर से कम आवक और बड़ी तेल मिलों द्वारा सरसों के दाम 200-300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाये जाने के बाद सरसों तेल-तिलहन कीमतों में आई तेजी के असर से देश के तेल-तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को अधिकांश तेल-तिलहनों के दाम मजबूत हो गये। सामान्य कामकाज के बीच मूंगफली तेल-तिलहन के भाव स्थिर रहे। मलेशिया एक्सचेंज में 3.30 बजे लगभग 1.75 प्रतिशत की तेजी थी। शिकॉगो एक्सचेंज में कल रात लगभग 2.5 प्रतिशत की तेजी थी और फिलहाल भी यहां सुधार जारी है।

पश्चिम रेलवे
सामग्री प्रबंधन विभाग
ई–नीलामी बिक्री कार्यक्रम में संशोधन
पी. वे और अन्य विभिन्न स्क्रैप के लिए मार्च 2026 में अतिरिक्त ई–नीलामी बिक्री कार्यक्रम

कृपया इस कार्यालय की ई–नीलामी बिक्री अधिसूचना संख्या **SIII/Auction Programme–1/मार्च–2026, दिनांक 06.02.2026** देखें। निम्नलिखित डिपो के लिए **मार्च 2026** में आयोजित होने वाले रेलवे स्क्रैप सामग्री के निपटान हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त ई–नीलामी कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

डिपो	मार्च, 2026 के लिये अतिरिक्त ई–नीलामी कार्यक्रम	मंडल प्रभारी अधिकारी	संपर्क सूत्र
मुंबई सेंट्रल	30.03.2026	सी. डिवीजनल मटेरियल्स मैनेजर– मुंबई सेंट्रल	02223094142 09004499006

अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया **पश्चिम रेलवे** के सामग्री प्रबंधन विभाग की वेबसाइट wr.indianrailways.gov.in और www.ireps.gov.in ई–नीलामी पोर्टल देखें।
(SIII/Auction Programme–3/मार्च–2026, दिनांक 26.03.2026) 1267

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/04/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
इंदौर, जवाहर राज मोहल्ला, 125590700059520, विजय नगर इंदौर, 124550700037106,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/– रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.